VAJIRAO & REDDY INSTITUTE
India's Top Potential Training Institute for IAS
+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(20 September 2023)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023': इसे लागू करने से पहले आगे का रास्ता क्या है?
- ग्रीन नज (Green Nudge): लोगों में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक सौम्य प्रेरणा
- वित्त मंत्री ने विश्वसनीय फसल उपज अनुमान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया
- WHO की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट से पता चलता है कि बेहतर नियंत्रण से 2040 तक भारत में 46 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है

‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’: इसे लागू करने से पहले आगे का रास्ता क्या है?

संदर्भ:

- केंद्र सरकार द्वारा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2023 या नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया।
- उल्लेखनीय है महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रयास 1990 के दशक के मध्य से ही चल रहे हैं। भले ही पेश किया गया विधेयक संसद के दोनों सदनों में तेजी से पारित हो जाए, लेकिन इसे लागू होने में कुछ समय लग सकता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

लोकसभा में पेश हुए विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- संविधान (128वां) संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार, "जितना संभव हो, लोक सभा के लिए सीधे चुनाव द्वारा भरी जाने वाली सीटों की कुल संख्या का एक तिहाई (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित), महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा"। यह विधेयक राज्यों और दिल्ली में विधानसभाओं के लिए समान प्रावधान का प्रस्ताव करता है।
- इस विधेयक के अनुसार संविधान में नए अनुच्छेद - 330Aऔर 332A - पेश करने का प्रस्ताव करता है। ये नए प्रावधान क्रमशः लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बदलाव पेश करेंगे।
- उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में, एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी लेकिन, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोई अलग आरक्षण नहीं है।
- इस विधेयक में एक निर्णायक खंड (सनसेट कॉल्ज) है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- यह विधेयक महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को परिसीमन प्रक्रिया पर निर्भर बनाता है, और प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों में परिवर्तन किया जाएगा।

पहली बार में और बाद में आरक्षित सीटों की पहचान कैसे की जाएगी?

- इस विधेयक में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालाँकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि इन सीटों की पहचान कैसे की जाएगी।
- यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक अपने प्रकृति में सक्षमकारी (Enabling) है। दूसरे शब्दों में, यह सरकार को इसके कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि सीटों का निर्धारण एक अलग कानून द्वारा किया जाएगा जिसे सरकार पेश करेगी।

वर्तमान में SC और ST के लिए आरक्षित सीटें कैसे तय की जाती हैं?

- परिसीमन अधिनियम, 2002 सीटों को आरक्षित करने के लिए व्यापक सिद्धांत बताता है।
- इस अधिनियम के तहत नियुक्त परिसीमन आयोग जनसंख्या के आधार पर आरक्षित किए जाने वाले संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करने के लिए जिम्मेदार है।
- इस प्रक्रिया में किसी राज्य के लिए आरक्षित सीटों को उस राज्य की जनसंख्या में SC व ST की आबादी के अनुपात में समान रूप से वितरित किया जाता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

महिला आरक्षण की योजना को क्रियान्वित करने के लिए किन संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी?

- परिसीमन के लिए - जो आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्व शर्त है - संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन करना होगा।
- अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के निर्वाचन क्षेत्रों (संख्या और सीमाओं) के पुन: समायोजन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 170(3) विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है।

इस कदम (महिला आरक्षण) को अभी कई विधायी बाधाओं से गुजरना होगा:

- नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023, महिला आरक्षण को विवादास्पद परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण इस विधेयक के शुरू होने के बाद पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा।
- संविधान का अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों (संख्या और सीमाओं) के पुन: समायोजन का प्रावधान करता है।
- लेकिन 42वें संविधान संशोधन, 1976, ने 2000 के बाद पहली जनगणना प्रकाशित होने तक इस परिसीमन अभ्यास को रोक दिया। 2001 में इसे 25 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इसलिए अब 2026 के बाद पहली जनगणना के नतीजों पर परिसीमन होगा।

- सामान्य तौर पर, इसका मतलब यह होगा कि परिसीमन 2031 की जनगणना के परिणाम प्रकाशित होने के बाद ही होगा। लेकिन चूंकि 2021 में होने वाली जनगणना में देरी हुई है, जाहिरा तौर पर कोविड महामारी के कारण, इस समय रेखा में बदलाव किया जा सकता है।
- जनगणना प्रक्रिया अब जल्द से जल्द 2025 में हो सकती है। यदि '2021 जनगणना' के परिणाम 2026 के बाद प्रकाशित होते हैं, तो यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार बन सकता है।
- जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया होगी जिसके लिए संविधान में और अधिक संशोधन की आवश्यकता है।
- भारत के चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार एस के मेंदीरत्ता ने कहा कि विधान सभाओं की संरचना से संबंधित अनुच्छेद 82 और 170 (3) में संशोधन करना होगा। परिसीमन प्रक्रिया के लिए राज्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होगी।
- उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में किसी भी बदलाव को उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित करना होगा, और कम से कम आधे राज्य द्वारा इसकी पुष्टि की आवश्यकता होगी।

'ग्रीन नज (Green Nudge)': लोगों में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को प्रभावित करने के लिए एक सौम्य प्रेरणा

संदर्भ:

- चीन में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के सहयोग से किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि "नो डिस्पोजेबल कटलरी" को ऑर्डर के लिए डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाने और ग्राहकों को "ग्रीन पॉइंट्स" से पुरस्कृत करने से नो-कटलरी ऑर्डर की हिस्सेदारी में 648% की वृद्धि हुई। अध्ययन में कहा गया है कि इस कदम से पर्यावरण को महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं।

'ग्रीन नज (Green Nudge)' क्या होता है?

- 'ग्रीन नज' लोगों में पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को प्रभावित करने के लिए सौम्य अनुनय हैं।
- व्यवहारिक अर्थशास्त्र में, 'Nudge Theory' ऐसे हस्तक्षेप हैं जो लोगों के लिए उपलब्ध विकल्पों को प्रतिबंधित किए बिना कुछ निर्णय लेने के लिए उनकी पसंद को प्रभावित करते हैं।

अध्ययन में Green Nudge को लेकर क्या निष्कर्ष निकला:

- अलीबाबा के साथ अध्ययन से ऐसी विशेषताएं सामने आईं जो अवधारणा पर पहले से उपलब्ध साहित्य से इसके तहत Green Nudge को अलग करती हैं। ऐतिहासिक रूप से, Nudges Theory अल्पकालिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अलीबाबा अध्ययन ने व्यक्तियों के आदेश देने वाले व्यवहार के माध्यम से अपना निरंतर प्रभाव दिखाया।
- चालाकी पूर्ण होने के कारण अतीत में "नज थ्योरी" की आलोचना की जाती रही है, क्योंकि वे हमेशा पारदर्शी नहीं होते हैं और कभी-कभी काम करने के लिए लोगों में अज्ञानता या जागरूकता की कमी पर निर्भर हो सकते हैं।

- लेकिन इस अध्ययन पर काम कर रहे शोधकर्ताओं ने कहा है कि उनके द्वारा लागू किए गए 'ग्रीन नज' उपयोगकर्ताओं के लिए समझने में आसान और पारदर्शी हैं।

क्या भारत में 'ग्रीन नज' काम करते हैं?

- ज़ोमैटो, भारत में एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफ़ॉर्म है, इसके ऐप पर भी इसी तरह के नियम हैं। जबकि कंपनी का कहना है कि कटलरी को छोड़ने का विकल्प उसके प्लेटफॉर्म पर हमेशा उपलब्ध था, उसने अगस्त 2021 में डिफ़ॉल्ट चयन को "नो-कटलरी" में बदल दिया।
- ज़ोमैटो की नो-कटलरी पहल न केवल प्लास्टिक बल्कि समग्र सामग्री अपशिष्ट को कम करने के लिए डिज़ाइन की गई थी।
- डेटा बताता है कि हर पांच में से तीन ऑर्डर कटलरी प्राप्त करने से इनकार करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब तक कटलरी कचरे में अनुमानित 1,000 मीट्रिक टन की कमी आई है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

वित्त मंत्री ने विश्वसनीय फसल उपज अनुमान की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया:

चर्चा में क्यों है?

- वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 सितंबर को दलहन और तिलहन से लेकर सभी आवश्यक फसलों की संभावित पैदावार का वास्तविक समय पर आकलन करने की जोरदार वकालत की।

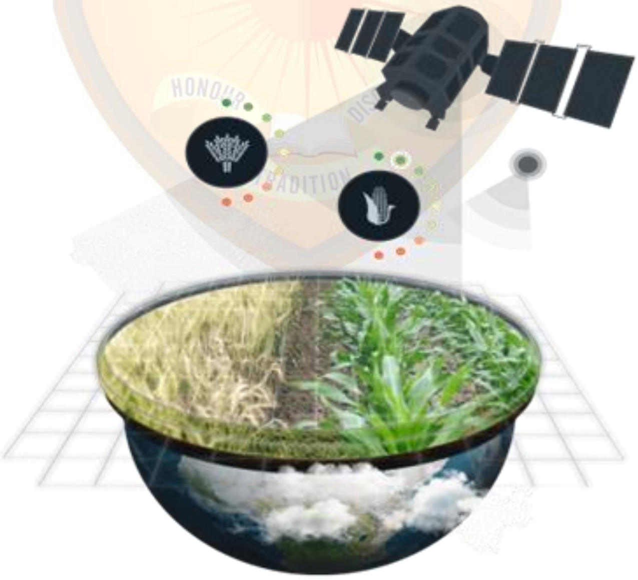

- इससे जुड़े विश्वसनीय कृषि उत्पादन अनुमान के आभाव में, भारत को अक्सर आयात करने की आवश्यकता पड़ती है, तथा जिसका प्रभाव भारतीय किसानों पर हानिकारक रूप से पड़ता है।

प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH):

- वित्त मंत्री ने गेहूं और चावल की फसल के लिए इस ख़रीफ़ सीज़न से YES-TECH नामक एक नई स्वचालित वास्तविक समय उपज अनुमान प्रणाली के संदर्भ में उल्लेख किया कि "अब तक हम अनुमान लगा सकते थे कि कितनी भूमि गेहूं के अंतर्गत आ रही है, लेकिन क्या हम जानते थे कि उत्पादन क्या होगा? क्या हमारे पास फसल का वास्तविक समय मूल्यांकन अनुमान प्रणाली थी? लेकिन अब ऐसा संभव होने की उम्मीद है"।
- उन्होंने कहा कि इसरो और ICAR की सहायता से बनाई गई YES-TECH प्रणाली को जल्द से जल्द अन्य फसलों, विशेष रूप से दलहन और तिलहन को कवर करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए।
- इससे अर्थव्यवस्था को बेहतर मदद मिलेगी ताकि हम जरूरत पड़ने पर अपने आयात की योजना बना सकें, यह सुनिश्चित कर सकें कि हमारी आयात या निर्यात नीति के कारण किसान को नुकसान न हो।
- उल्लेखनीय है कि YES-TECH एक प्रौद्योगिकी-संचालित उपज अनुमान प्रणाली है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन के लिए कार्यप्रणाली, सर्वोत्तम अभ्यास और एकीकरण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YES-TECH को अपनाने का संभावित लाभ:

- उल्लेखनीय है कि यह देश दालों का आयात करता रहा है और कभी-कभी जब दालों की कमी हमारे सामने आती है तो हम परेशान हो जाते हैं। यदि हमारे पास वास्तविक समय में इस बात का आकलन हो कि कितनी मात्रा में बोया जा रहा है, उस समय भी और संभावित उत्पादन का अनुमान हो, तो हम पहले से योजना बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे कि यदि कोई कमी होने वाली है, तो हम जानते हैं कि कहां से प्राप्त करना है।
- हम अंतिम समय में किसान की उपज की कीमत को कम नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि उस समय हमें कमी का आकलन मिलता है और हमें इसे आयात करने की आवश्यकता होती है। जैसे ही 'आयात' शब्द आता है, सबसे पहली चीज़ जो घटित होती है वह यह कि किसान को अपनी उपज के लिए जो कीमत मिलनी होती है वह गिर जाती है।
- उल्लेखनीय है कि वास्तविक समय के अनुमान प्राप्त होने से ऐसी "अप्रिय अनिवार्यता (आयात करने की मजबूरी)" जिससे हमारे किसानों का नुकसान होता है, से बचने में मदद मिलेगी।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

WHO की उच्च रक्तचाप रिपोर्ट से पता चलता है कि बेहतर नियंत्रण से 2040 तक भारत में 46 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है:

संदर्भ:

- उच्च रक्तचाप के वैश्विक प्रभाव पर डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई पहली रिपोर्ट के अनुसार, अगर भारत की उच्च रक्तचाप से ग्रस्त आधी आबादी अपने रक्तचाप को नियंत्रित कर ले तो 2040 तक भारत में कम से कम 46 लाख मौतों को रोका जा सकता है।

- इसका अनुमान है कि देश की 30 से 79 आयु वर्ग की कुल आबादी का 31 प्रतिशत आबादी या 18.83 करोड़ लोग वर्तमान में इस स्थिति के साथ जी रहे हैं।

WHO रिपोर्ट का भारत को लेकर प्रमुख निष्कर्ष:

- उच्च रक्तचाप (140/90) को ध्यान में रखते हुए स्ट्रोक, दिल का दौरा, दिल की विफलता, गुर्दे की क्षति और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं और इसे रोका जा सकता है।
- उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 37 प्रतिशत भारतीयों का ही निदान हो पाता है और केवल 30 प्रतिशत ही इलाज करा पाते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, देश में उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 15 प्रतिशत लोगों में ही यह नियंत्रण में है।

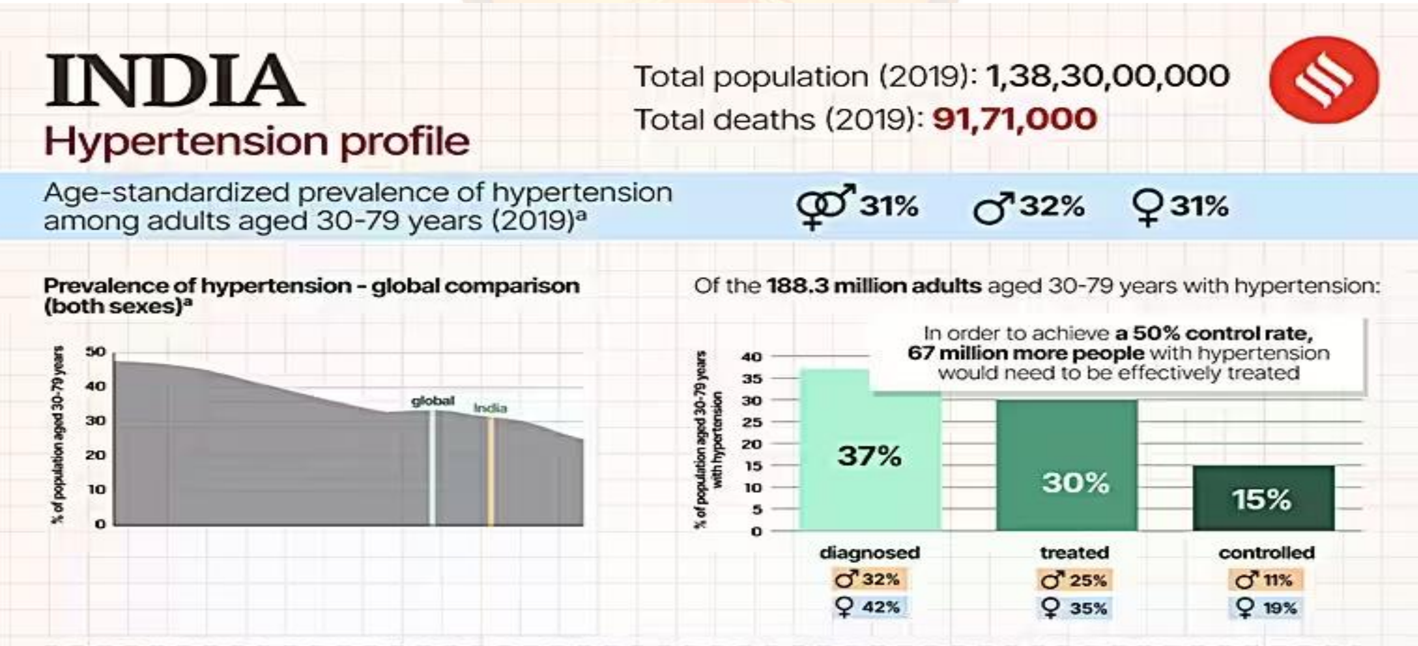

- वास्तव में, इसमें कहा गया है, देश में दिल का दौरा जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली आधी से अधिक मौतों (52 प्रतिशत) का कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

युवा आबादी के लिए रिपोर्ट का क्या मतलब है?

- चूंकि भारतीयों में अन्य देशों की तुलना में एक दशक पहले हृदय रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है और युवाओं में दिल के दौरे की रिपोर्ट पहले आती है, इसलिए डब्ल्यूएचओ के निष्कर्ष महत्वपूर्ण हैं।
- अनियंत्रित उच्च रक्तचाप रक्त वाहिकाओं और अंगों को नुकसान पहुंचाता है और लंबे समय तक हृदय तनाव के संपर्क में रहने से यह प्रभाव बढ़ जाता है।
- इसलिए यदि युवा लोगों का उच्च रक्तचाप का पता नहीं चल पाता है या अनियंत्रित हो जाता है, तो उन्हें भविष्य में प्रतिकूल स्वास्थ्य घटनाओं का खतरा अधिक होता है।
- हमारी आबादी में मधुमेह (10.1 करोड़) और प्री-डायबिटीज (13.7 करोड़) के उच्च स्तर को देखते हुए, अनियंत्रित उच्च रक्तचाप स्वास्थ्य जटिलताओं की जंगल की आग को भड़का सकता है।
- हालांकि, हमारे रहन-सहन की आदतों को बदलकर और जरूरत पड़ने पर दवाओं का अतिरिक्त उपयोग करके प्रभावी नियंत्रण से इन जोखिमों को काफी हद तक रोका जा सकता है।
- जबकि भारत ने 2025 तक उच्च रक्तचाप या मधुमेह के 75 मिलियन रोगियों को मानक देखभाल पर रखने का निर्णय लिया है, इस तथ्य की डब्ल्यूएचओ ने सराहना की है।

भारत में उच्च रक्तचाप के प्राथमिक कारक क्या हैं?

- भारत में उच्च रक्तचाप के प्राथमिक ट्रिगर को उच्च नमक का सेवन, तंबाकू का उपयोग, मोटापा, शराब का सेवन और शारीरिक व्यायाम की कमी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- वास्तव में, रिपोर्ट ने भारत में तंबाकू के उपयोग (28 प्रतिशत) और शारीरिक निष्क्रियता (34 प्रतिशत) को दो सबसे शक्तिशाली ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया है।

क्या किया जाने की जरूरत है?

- रिपोर्ट से पता चलता है कि उच्च रक्तचाप की रोकथाम, शीघ्र पता लगाना और प्रभावी प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल में सबसे अधिक लागत प्रभावी हस्तक्षेपों में से एक है।
- लोगों द्वारा खुद का युवा आबादी सहित रक्तचाप का नियमित जाँच करते रहना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह पर दवाएं भी लेनी चाहिए।
- आहार संबंधी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना जो, लोगों को भोजन में नमक कम करने और फलों और सब्जियों (जिनमें रक्तचाप कम करने वाला पोटेशियम होता है) की खपत बढ़ाने में मदद करता है।
- शराब के सेवन से बचना चाहिए या बहुत कम कर देना चाहिए, क्योंकि यह उच्च रक्तचाप को बढ़ाता है या बनाए रखता है और प्रभावी नियंत्रण को बहुत कठिन बना देता है।

+918171181080
+919068806410
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- शारीरिक गतिविधि, अच्छी नींद की आदतें, वायु प्रदूषण के संपर्क में कमी से रक्तचाप को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही योग, ध्यान और संगीत जैसे तनाव से निपटने में भी मदद मिलेगी।
- प्रौद्योगिकी सक्षम फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे आशा और एएनएम, उच्च रक्तचाप का शीघ्र पता लगाने और दीर्घकालिक प्रबंधन में बहुत प्रभावी हो सकते हैं।